

प्रेषक

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/  
एडीशनल कमिश्नर, नोएडा  
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

(वाद अनुभाग)

लखनऊ:दिनांक: ०९ मार्च, 2021

विषय:-प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद में रिट दायर करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या 2103 दिनांक 11.03.2019 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा समस्त हेतु यह निर्देश दिये गये थे कि पूर्व से जोनल स्तर पर गठित विधि समिति जी०एस०टी० से सम्बन्धित मामलों में भी इन्टरनल रिव्यू सेल के रूप में कार्य करेगी। वर्तमान में जी०एस०टी० अपीलिएट टिब्यूनल का गठन नहीं हो पाया है, अतः ऐसे सभी मामले जिसमें सम्बन्धित अधिकारी मा० उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दाखिल करना आवश्यक पाते हैं तो तत्काल विधि समिति (इन्टरनल रिव्यू सेल) से परीक्षण कराकर, स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय कार्य से राय प्राप्त कर प्रकरण रिट योग्य पाये जाने पर उचित माध्यम से मुख्यालय/शासन से स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा उक्त के आधार पर उच्च न्यायालय कार्य के माध्यम से मुख्य स्थायी अधिवक्ता से सम्पर्क कर रिट सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

प्रश्नगत विषय के सन्दर्भ में वाणिज्य कर मुख्यालय स्तर पर गठित विधि समिति की बैठक दिनांक 26.07.2019 को सम्पन्न हुयी थी। विधि समिति का मत है कि मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका हेतु प्राप्त हो रहे अत्यधिक मामलों को देखते इस बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है कि केवल महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न अन्तर्वलित होने के मामले में रिट याचिका दाखिल की जाए तथा जिन मामलों में वाहन एवं माल को अभी तक रोके रखा गया है अथवा किसी अन्य कारण से शीघ्रता अपेक्षित है, उन्हीं में रिट की जाए। एडी०कमि० ग्रेड-1, वा०क० जोन इन समस्त बिन्दुओं पर परीक्षण कर तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही रिट का प्रस्ताव भेजे तथा जिन मामलों में रिट नहीं की जाती है उनमें अपीलिएट टिब्यूनल के गठन होने पर आवश्यकतानुसार अपील दाखिल करायी जाए।

प्रश्नगत विषय के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन राज्य कर अनुभाग-2 के आदेश संख्या -76/XI-2-9(42)17/2020 दिनांक 14.01.2020 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्न प्रकार व्यवस्था की गयी है:-

1-Short title - This Order may be called Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Twelfth Removal of Difference) order, 2020.

2-For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating-

(a) The "three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" in sub-section(1) of section 112, the start of the three months period shall be considered to be the later of the following dates:-

(1) Date of communication of order; or

(2) The date on which the President of the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office;

(b) the "six months from the date on which the said order has been passed" in sub section (3) of section 112, the start of the six months period shall be considered to be later of the following dates:-

(1) date of communication of order ; or

(2) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.

स्पष्ट है कि किसी भी मामले में न्यायाधिकरण के गठन के 6 माह के अन्दर अपील किए जाने का विकल्प उपलब्ध है।

अपील संख्या-01/2018, वर्ष 2017-18 सर्वश्री के० पान फ्रेगरेन्स प्रा०लि० बनाम असिस्टेंट कमिश्नर, वा०क० (सचल दल)-प्रथम इकाई बरेली अन्तर्गत धारा-129 (3) के मामले में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील)-प्रथम, वाणिज्य कर, बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2018 के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट योजित करने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या- 376/11.02.2019-14(151)/2019 दिनांक 04.02.2020 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी। प्रकरण में श्री वी०के० पाण्डेय मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल इकाई को अपने पत्र संख्या 1637ए दिनांक 17.08.2020 (प्रति संलग्न) प्रेषित करते हुए निम्न अभिमत प्रकट किया गया है-

"THE MATTER WAS PLACED BEFORE ME FOR FILING THE WRIT PETITION BEFORE THIS HON'BLE COURT AGAINST THE ORDER PASSED BY THE 1<sup>st</sup> APPELLATE ON 07.02.2018 BY WHICH THE 1<sup>st</sup> APPELLATE AUTHORITY HAS SET-ASIDE THE PENALTY ORDER PASSED U/s 129(3) GOODS AND SERVICE TAX ACT 2017 AND THE GOODS WERE DIRECTED TO BE RELEASED WITHOUR ANY SECURITY. I HOPE THAT GOODS MUST HAVE BEEN RELEASED BY NOW. AGAINST THE ORDER PASSED BY ON 1<sup>st</sup> APPELLATE AUTHORITY THE APPEAL IN MAINTAINABLE BEFORE THE COMMERCIAL TAX TRIBUNAL U/s 112 OF THE GST ACT.

A GOVT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE VIDE ORDER NO 09 2019(CENTRAL ACT) DATED 03.12.2019 HAS PRESCRIBED THAT FOR THE

REMOVAL OF DIFFICULTIES ITS HEREBY CLARIFIED THAT FOR THE PURPOSE OF CALCULATING A-3 MONTHS FROM THE DATE ON WHICH THE ORDER SHORT TO BE APPEAL AGAINST IS COMMUNICATION TO A PERSON PREFERRING THE APPEAL IN SUB SECTION 1 OF SECTION 112, THE START OF 3 MONTHS PERIOD SHALL BE CONSIDERED TO BE LETTER OF THE FOLLOWING DATED (1) THE CASE MAY BE OF THE APPELLATE TRIBUNAL AFTER ITS CONSTITUTION U/S 109. INTERES THE OFFICE THEREFORE AGAINST THE ORDER PASSED BY THE 1<sup>st</sup> APPELLATE AUTHORITY THE APPEAL IS MAINTAINABLE U/S 112 AS AND WHEN THE TRIBUNAL IS CONSTITUTED AND THE LIMITATION IS EXTENDED TILL THE CONSTITUTION OF THE TRIBUNAL. ON SIMILAR FACT THIS HON'BLE COURT IN THE CASE OF WRIT TAX NO. 291/2020 POLO INTERNATIONAL Vs. STATE AND OTHTER'S (Enclosed) HAS DISPOSED OFF THE WRIT PETITION FILED BY THE DEALER BY HOLDING THAT AND WHEN THE TRIBUNAL IS CONSTITUTED THE DEALER CAN FILE."

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में अति आवश्यक होने पर ही रिट का प्रस्ताव एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर द्वारा स्वयं की पूर्ण संतुष्टि उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रेषित किया जाएगा, यदि किन्ही मामलों में बिना सम्यक आधार/आवश्यकता के रिट दाखिल करने पर कोई विपरीत न्यायिक टिप्पणी/आदेश प्राप्त होता है तो उक्त हेतु सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।

कृपया उक्त से स्वयं एवं सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



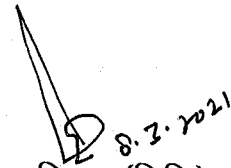
(अमृता सोनी)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश

पू0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 प्रभार ज्वा0कमि0(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उपरोक्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश लखनऊ



प्रति,

कमिश्नर वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

एडीशनल कमिश्नर, सेड-2(वि0अनु0शा0)  
वाणिज्य कर, झॉरसी जोन, झॉरसी

(वाद अनुभाग)  
महोदय,

लखनऊ:दिनांक: // मार्च, 2019

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 325 दिनांक 02.02.2019 का सम्बन्ध ग्रहण करने का नोट करें, जिसके द्वारा प्रथम अपीलवादी आदेशों के विरुद्ध किंग मामलों में रिट याचिका संजित की जाती है, इसका परीक्षण किंग स्तर के अधिकारी द्वारा या किंग समिति द्वारा किया जायेगा, के विन्दु पर स्थिति स्पष्ट करायें जाने की अपील की गयी है।

झॉरसी जोन से सम्बन्धित अपील संख्या 56/2019 सर्वश्री रातारार ट्रीडिंग कम्पनी, कोसवपुरम, गड्डि बिल्डो वनाड उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक 31.01.2019 के आदेश के विरुद्ध रिट दाखल करने हेतु मुख्य स्थायी अधिकारता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अरि0कगि0, वाणिज्य कर, सचल दल घिसौरी लखितपुर द्वारा पत्र दिनांक 27.02.2019 द्वारा विधिक राय माँगी गयी थी। इस मामले में श्री सी0वी0 त्रिपाठी विशेष अधिकारता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दी गयी विधिक राय में समस्त प्रक्रियात्मक विन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की गयी है। विधिक राय में उल्लिखित है कि वाद से सम्बन्धित अधिकारी, जोनल स्तर पर गठित विधि समिति के माध्यम से कमिश्नर, वाणिज्य कर, से उक्त हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा, परन्तु इतरां शारान के न्याय विभाग से भी रिट दाखल हेतु आवश्यक अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी। आपके जोन द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27.02.2019 पर श्री सी0वी0 त्रिपाठी, विशेष अधिकारता की विधिक राय (प्रति संलग्न) से भी स्पष्ट है कि सम्बन्धित अधिकारी मामले की उपरोक्त स्तर पर गठित विधि समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा विधि समिति द्वारा उपरोक्त मामलों में रिट दाखल किये जाने की अनुशंसा करने पर स्थायी अधिकारता, उच्च न्यायालय कार्य से राय प्राप्त कर उक्त की उचित माध्यम से कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 को प्रेषित करेगा। पुनः शारान तथा न्याय विभाग की अनुमति से उक्त मामले में रिट दाखल करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही उच्च न्यायालय कार्य के अधिकारियों के सहयोग से की जायेगी। कृपया उपरोक्त से अवगत होत हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रकरण के आलोक में समस्त हेतु यह निर्देशित किया जाता है कि पूर्व से जोनल स्तर पर गठित विधि समिति जी0एरा0टी0 से सम्बन्धित मामलों में भी इन्टरनल रिब्यू सोल के रूप में कार्य करेंगी। वर्तमान में जी0एरा0टी0 अपीलिएट ट्रिब्यूनल का गठन नहीं हो पाया है, अतः ऐसे सभी मामलों जिसमें सम्बन्धित अधिकारी मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दाखिल करना आवश्यक पाते हैं तो तत्काल विधि समिति (इन्टरनल रिब्यू सोल) से परीक्षण कराकर, स्थायी अधिकारता, उच्च न्यायालय कार्य से राय प्राप्त कर प्रकरण रिट योग्य पाये जाने पर उचित माध्यम से मुख्यालय/शारान से स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा उक्त के आधार पर उच्च न्यायालय कार्य के माध्यम से मुख्य स्थायी अधिकारता से सम्पर्क कर रिट सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।  
संलग्नकः--उपरोक्तानुसार।

(अजीत कुमार शुक्ला)  
एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर  
उ0प्र0, लखनऊ

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- समस्त एडीशनल कमिश्नर सेड-1, जोन/उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
- 2- ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)/(कार्य0) वाणिज्य कर, झॉरसी जोन, झॉरसी

ज्वाइंट कमिश्नर(वाद)वाणिज्य कर  
मुख्यालय, लखनऊ

## **Uttar Pradesh Shasan Rajya Kar Anubhag -2**

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Order No.-76 2020 dated January 14, 2020.

### **ORDER**

---

**No.-76/XI-2-9(42)/17-2020  
Lucknow : Dated : January 14, 2020**

---

WHEREAS sub-section (1) of section 112 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no 1 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the Central Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 112 of the said Act provides that the Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of Central tax or Commissioner of Union territory tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order;

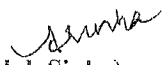
AND WHEREAS, section 109 of the said Act provides for the constitution of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal and Benches thereof;

AND WHEREAS, for the purpose of filing the appeal or application as referred to in sub-section (1) or sub-section (3) of section 112 of the said Act, as the case may be, the Appellate Tribunal and its Benches are yet to be constituted in the State under section 109 of the said Act as a result whereof, the said appeal or application could not be filed within the time limit specified in the said sub-sections, and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:---

1. Short title.---This Order may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Twelfth Removal of Difficulties) Order, 2020.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that for the purpose of calculating,-
  - (a) the "three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal" in sub-section (1) of section 112, the start of the three months period shall be considered to be the later of the following dates:-
    - (i) date of communication of order ;or
    - (ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office;
  - (b) the "six months from the date on which the said order has been passed" in sub-section (3) of section 112, the start of the six months period shall be considered to be the later of the following dates:-
    - (i) date of communication of order; or
    - (ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.

By Order,

  
(Ajok Sinha)

Apar Mukhya Sachiv

From,

B.K. PANDEY  
Standing Counsel,  
High Court, Allahabad

To,

Assistant Commissioner,  
Commercial Tax, Mobile Squad  
Unit-1, Bareilly

File No. 1637 A

Dated:- 17-08-2020

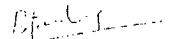
Sub:- In the matter of S/s Kay, Pan Fragrance Pvt. Ltd B-15 Bulandshahr Road, Industrial Area Ghaziabad Vs. Assistant Commissioner, State Tax, Mobile Squad Unit-1 Bareilly in Appeal No.-BLY/001/2018 for the Assessment Year 2017-18

The matter was placed before me for filling the writ petition before this Hon'ble Court against the order passed by the 1<sup>st</sup> Appellate Authority on 7.02.2018 by which the 1<sup>st</sup> Appellate Authority has set-aside the penalty order passed U/S 129(3) of the U.P. Goods and Service Tax Act 2017 and the Goods were directed to be released without any security. I hope that goods must have been released by now.

Against the order passed by the 1<sup>st</sup> Appellate Authority the appeal is maintainable before the Commercial Tax Tribunal U/s 112 of the GST Act.

A Govt. of India Ministry of Finance vide order no. 9 of 2019 (Central Act) dated 03.12.2019 has prescribed that for the removal of difficulties its hereby clarified that for the purpose of calculating A-3 months from the date on which the order short to be appeal against is communicated to a person preferring the appeal in sub Section 1, of Section 112, the start of 3 months period shall be considered to be later of the following dated-(1) Date of communication of order, (2) The date on which the president or the State President as the case may be of the appellate tribunal after its constitution U/s 109, interest the office, therefore against the order passed by the 1<sup>st</sup> Appellate authority the appeal is maintainable U/s 112 as and when the tribunal is constituted and the limitation is extended till the constitution of the tribunal. On similar fact this Hon,ble court in the case of Polo International Vs. State and others has disposed off the Writ petition filed by the dealer by holding that and when the tribunal is constituted the dealer can file. A copy of the said judgment is annexed along with the proposal.

Your Sincerely

  
(B.K.PANDEY)

Standing Counsel,  
High Court, Allahabad

Court No. - 42

Case :- WRIT TAX No. - 291 of 2020

Petitioner :- M/S Polo International Through Its Proprietor Shri Ashutosh Sajjan Agarwal

Respondent :- State Of U.P., Through Secretary, Institutional Finance, Civil Secretariat, U.P. Govt. And 2 Others

Counsel for Petitioner :- Rishi Raj Kapoor

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Manoj Kumar Gupta, J.

Heard Sri Rishi Raj Kapoor, learned counsel for the petitioner and Sri B.K. Pandey, learned Standing Counsel for the State respondents.

The petitioner has preferred the instant petition under Article 226 of the Constitution challenging the order dated 26.11.2019 passed in Appeal No.GST-03/19 by respondent no.2 under Section 129 (3) of the U.P. G.S.T. Act and C.G.S.T. Act, 2017/ Section 20 of the IGST Act, 2017 and tax and penalty order No.228 dated 5.9.2018 passed by respondent no.3 under Section 129 (3) of the U.P. G.S.T. Act and C.G.S.T. Act, 2017/ Section 20 of the IGST Act, 2017 and has also prayed for a direction to respondent no.3 to refund the amount of Rs.31,304/- deposited at the time of filing of appeal before respondent no.2.

It is not disputed that the impugned orders are appealable under Section 112 of the C.G.S.T. Act, 2017. The appeal is to be filed within 90 days from the date on which the order sought to be appealed is communicated to the person preferring the appeal.

The instant petition has been filed by-passing the remedy of appeal under Section 112 of the Act on the ground that the appellate tribunal has not been constituted till date.

It has been pointed out by learned standing counsel that the Government, having regard to the difficulty faced by the assesseees in filing appeal on account of non-constitution of the Tribunal and its Benches in various States and Union Territories, has issued Central Goods and Service Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019 notified in the Gazette of India dated 3rd December, 2019 stipulating that in such a situation, the three months' period shall be considered to be the date on which the President of the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under Section 109, enters office. It is urged that in such circumstances, the petitioner can wait and avail the remedy of filing appeal as and when the Tribunal is constituted. It is also



pointed out that since the seized goods have already been released, therefore, no prejudice is going to be caused to the petitioner at the present moment.

Learned counsel for the petitioner very fairly admits the above legal position and also the fact that the goods have already been released.

In view of the above, the instant petition is disposed of by providing that the petitioner can invoke the remedy of filing appeal before the Tribunal in terms of the provisions of the Central Goods and Services Tax (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019.

(Manoj Kumar Gupta, J)

Order Date :- 8.6.2020

SL